राजस्थान राज्य

बनाम

राम चन्द्र

12 अप्रैल 2005

[अरिजीत पसायत और एस.एच. कपाड़िया, न्यायमूर्तिगण]

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – धारा 50:

दायरा – धारित की अभिनिर्धारित: धारा 50 केवल आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होती है – वाहन या कंटेनर या बैग या परिसर की तलाशी तक इसका विस्तार नहीं होता है।

व्यक्तिगत खोज:

वरिष्ठ अधिकारियों की किसी भी सूचीबद्ध श्रेणी की उपस्थिति में आरोपी की तलाशी लेने का विकल्प — प्रयोजन और उद्देश्य – यह कष्टप्रद तलाशी, अनुचित व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है और निर्दोषों के हितों की रक्षा करता है।

अभियुक्त को दिया गया विकल्प केवल यह चुनना है कि क्या वह तलाशी लेने वाले अधिकारी द्वारा या निकटतम उपलब्ध राजपत्रित अधिकारी या निकटतम उपलब्ध दंडाधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहेगा – निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम दंडाधिकारी की पसंद का प्रयोग, तलाशी लेने वाले अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि अभियुक्त द्वारा।

तलाशी का प्रस्ताव करने वाला अधिकारी स्वयं एक राजपत्रित अधिकारी है – वह न तो खोज करने वाले अधिकारी के रूप में और न ही आईएएस अधिकारी के रूप में, जिसकी उपस्थिति में खोज प्रभावित होती है, दोहरी भूमिका में कार्य नहीं कर सकता है।

प्राधिकृत अधिकारी ने आरोपी–प्रत्यर्थी को राजपत्रित पद के पुलिस अधिकारी, या निकटतम दंडाधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प दिया – उसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी का विकल्प चुना – अभिनिर्धारित: इस प्रकार की गई तलाशी धारा 50 का उल्लंघन नहीं करती – उच्च न्यायालय ने कहा कि तलाशी में धारा 50 का उल्लंघन हुआ क्योंकि पुलिस अधिकारी छापा मारने वाले पक्ष का सदस्य था, यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है – उच्च न्यायालय ने इस आधार पर पुलिस अधिकारी की ओर से पक्षपात मानने में गलती की कि वह अधिकृत अधिकारी के साथ था – किसी भी स्थिति में, तथ्यों पर, पक्षपात या पूर्वाग्रह का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वह आरोपी को हिरासत में लेने के बाद ही मौके पर पहुंचा था।

वर्तमान अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि हालांकि आरोपी–प्रत्यर्थी को अभियोजन पक्ष के गवाह 3– पुलिस उपाधीक्षक, राजपत्रित पद के एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प दिया गया था, लेकिन चूँकि अभियोजन पक्ष का गवाह–3 छापेमारी दल का सदस्य था, इसलिए उसकी उपस्थिति में तलाशी को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1. उच्च न्यायालय का यह मानना सही नहीं था कि अभियोजन पक्ष के गवाह –3 की उपस्थिति में तलाशी, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 50 की आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं थी। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 और 18 के संदर्भ में आरोपी–प्रत्यर्थी को दोषी ठहराने वाले विचारण न्यायालय के फैसले को बहाल किया जाता है।

2.1. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में लागू होती है। इसका विस्तार किसी वाहन या कंटेनर या बैग या परिसर की तलाशी तक नहीं है। यह तब लागू होता है जब धारा 42 के संदर्भ में अधिकृत अधिकारी को धारा 41, 42 और 43 के प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेनी होती है। यहां तलाशी के लिए अपने विकल्प का उपयोग करने के लिए खोजे जाने वाले व्यक्ति को, धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम दंडाधिकारी की उपस्थिति, सूचित करने की आवश्यकता होती है।

2.2. धारा 50 के तहत दी जाने वाली आवश्यक जानकारी को संप्रेषित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रपत्र निर्धारित या अभिप्रेत नहीं है। चूंकि कोई विशिष्ट तरीका निर्धारित या अभिप्रेत नहीं है, इसलिए न्यायालय को सूचना के स्वरूप को नहीं, बल्कि उसके सार को देखना होगा। धारा 50 की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है या नहीं यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर किया जाना है और इसका कोई व्यापक सामान्यीकरण और/या सीधा रास्ता नहीं हो सकता है।

पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, (1999) 6 एससीसी 172, संदर्भित।

कलेमा तुम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, जेटी (1999) 8 एससी 293; *गुरबख्श सिंह बनाम हरियाणा राज्य*, (2001) 3 एससीसी 28; *रघबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य*, (1996) 2 एससीसी 201; *प्रभा शंकर दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य*, (2003) एआईसमीक्षा आवेदनससीडब्ल्यू 6592; *मदन लाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य*, (2003) 6 सुप्रीम 382 और *श्रीमती कृष्णा कंवर@ ठकुराइन बनाम राजस्थान राज्य*, जेटी (2004) 1 एससी 597, पर निर्भर किया गया।

3.1. एनडीपीएस अधिनियम तलाशी लेने वाले व्यक्ति को इस आशय का सुरक्षा प्रदान करता है कि उसे किसी वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने की आवश्यकता हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी राजपत्रित अधिकारी या दंडाधिकारी हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सुविधाजनक रूप से उपलब्ध है। एनडीपीएस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि यदि कोई राजपत्रित अधिकारी, चाहे वह किसी विशेष पद का पुलिस अधिकारी ही क्यों न हो, आरोपी को हिरासत में लेते समय पास में मौजूद है, तो आरोपी से पूछा जा सकता है कि क्या वह उस अधिकारी या दंडाधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहेगा।

3.2. अभियुक्त को दिया गया विकल्प केवल यह चुनना है कि क्या वह तलाशी लेने वाले अधिकारी द्वारा या निकटतम उपलब्ध राजपत्रित अधिकारी या निकटतम उपलब्ध दंडाधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहेगा। निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम दंडाधिकारी का चयन तलाशी लेने वाले अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि आरोपी द्वारा। मौजूदा मामले में आरोपी को सभी विकल्पों से अवगत कराया गया और उसने खुद पुलिस उपाधीक्षक (अभियोजन पक्ष का गवाह –3) की मौजूदगी में तलाशी लेने का विकल्प चुना।

रघबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (1996) 2 एससीसी 201, पर निर्भर किया गया।

4. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष सही होते यदि तलाशी लेने का प्रस्ताव करने वाला अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होता और वह धारा 50 के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प देता। उस स्थिति में, धारा 50 की आवश्यकता पूरी नहीं होगी क्योंकि खोज को प्रभावित करने का प्रस्ताव करने वाला अधिकारी दोहरी क्षमता में कार्य नहीं कर सकता है; पहला किसी व्यक्ति की तलाशी के लिए धारा 42 के तहत अधिकृत अधिकारी के रूप में और दूसरा राजपत्रित अधिकारी के रूप में जिसकी उपस्थिति में आरोपी तलाशी का विकल्प चुन सकता है।

5. एनडीपीएस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि तलाशी एक वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में की जाती है, खोज में पारदर्शिता और प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए इसे कानून में एक सिद्धांत के रूप में नहीं माना जा सकता है कि यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी साथ होता है अधिकृत अधिकारी (जिसे उच्च न्यायालय ने छापेमारी दल का सदस्य बताया है) की स्थिति अलग होगी। उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि अधिकारी की ओर से पक्षपात हो सकता है क्योंकि वह अधिकृत अधिकारी के साथ था। ऐसी धारणा कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं है; पूर्वाग्रह या पक्षपात के प्रश्न को स्थापित करना होगा न कि अनुमान लगाना होगा।

एस जीवनाथम बनाम पुलिस निरीक्षक के माध्यम से राज्य, हस्तांतरित आवेदनन, **[2004] 5 एससीसी 230 और** *राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी, तिरुचिरापल्ली, हस्तांतरित आवेदनन बनाम जयपॉल*, **(2004) 5 एससीसी 223, संदर्भित।**

6.1. निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष यदि आवश्यक हो तो तलाशी लेने की आवश्यकता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन अधिकारियों पर तलाशी करने का कर्तव्य सौंपा गया है, वे उचित तरीके से आचरण करें और कोई नुकसान या गलत काम न करें जैसे कि आपत्तिजनक स्थिति पैदा करना। किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा दवा देना और किसी भी झूठे साक्ष्य को गढ़ने से रोकना। संक्षेप में प्रावधान का उद्देश्य कष्टप्रद खोज, अनुचित व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करना और निर्दोष व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है।

6.2. वास्तव में, गिरफ्तारी से बचने और जांच को शुरू में ही बाधित करने के लिए, जिससे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके, धारा 50 की उपधारा (3) में एक वैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। शक्ति दंडाधिकारी या राजपत्रित अधिकारी में निहित की गई है जिसके समक्ष संबंधित व्यक्ति को उप-धारा (2) के तहत की गई उसकी मांग पर लाया जाता है कि उसकी संतुष्टि पर कि तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं है, औपचारिक कार्यवाही के बिना उस व्यक्ति को तुरंत मुक्त कर दिया जाए। परिणामस्वरूप, तलाशी तभी होती है जब वह ऐसे व्यक्ति को सेवामुक्त करने से इंकार कर देता है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 541/2005

एसबी आपराधिक अपील संख्या 129/1997 में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 8.1.2002 से।

अपीलकर्ता की ओर से अरुणेश्वर गुप्ता, अतिरिक्त महा न्यायभिकर्ता, नवीन कुमार सिंह, सुश्री शिवांगी और अशोक के महाजन उनके साथ थे।

प्रत्यर्थी की ओर से लाखन सिंह चौहान और डॉ. कैलाश चंद।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायाधीश, अरिजीत पसायत, द्वारा- अनुमति प्रदान की गई।

राजस्थान राज्य ने एकल न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ, जयपुर के फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसमें कहा गया है कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 50 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है। उक्त निष्कर्ष इस आधार पर निकाला गया कि यद्यपि आरोपी प्रत्यर्थी को पुलिस उपाधीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह (अभियोजन पक्ष का गवाह–3) की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प दिया गया था, वह वास्तव में छापेमारी पक्ष का सदस्य था और, इसलिए, उनकी उपस्थिति में तलाशी को बिल्कुल भी अधिनियम की धारा 50 के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है, हालांकि वह एक राजपत्रित अधिकारी थे।

संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं:

8.9.1995 को प्रेम शकर मीना (अभियोजन पक्ष का गवाह –2), एस.एच.ओ. पुलिस स्टेशन, कोतवाली, बारां को मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के बारे में सूचना मिली, वे मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे और आरोपी प्रत्यर्थी को पकड़ लिया। सत्येन्द्र सिंह, डिप्टी एसपी (अभियोजन पक्ष का गवाह–3) भी वहां पहुंचे। इसके बाद, यह संदेह होने पर कि आरोपी प्रत्यर्थी के पास प्रतिबंधित सामग्री थी, एस.एच.ओ. ने उसे श्री सत्येन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक (अभियोजन पक्ष का गवाह–3) की उपस्थिति में अपनी तलाशी लेने के अपने अधिकार के बारे में सूचित किया, जो एक राजपत्रित अधिकारी थे, और वहां या किसी दंडाधिकारी की उपस्थिति में उपस्थित थे। आरोपी ने उप पुलिस अधीक्षक (अभियोजन पक्ष का गवाह–3) की मौजूदगी में अपनी तलाशी लेने पर सहमति जताई। तलाशी लेने पर रमेश चंद (अभियोजन पक्ष का गवाह–5) और राजेंद्र कुमार (अभियोजन पक्ष का गवाह–6) की मौजूदगी में उसके कब्जे से 570 ग्राम अफीम बरामद हुई। बरामद अफ़ीम में से; 30 ग्राम वजन का एक नमूना लिया गया और उसे सील कर दिया गया। बाकी बची अफीम को भी सील कर दिया गया। तदनुसार, आरोपी को गिरफ्तारी ज्ञापन प्रदर्श पी–5 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया और वसूली का ज्ञापन तैयार किया गया। इसके बाद एस.एच.ओ. ने एफआईआर प्रदर्श पी–4 के तहत मामला दर्ज किया और बरामद अफीम को 'मालखाने' में जमा करा दिया। जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए और नमूना फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा। रासायनिक परीक्षण करने पर, चिह्नित पैकेट में मौजूद नमूने में 5.43% मॉर्फिन वाले अफीम पोस्त के जमा हुए रस के मुख्य घटकों के लिए सकारात्मक परीक्षण दिया गया।

इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, आरोपी पर अधिनियम की धारा 8 और 18 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। परीक्षण न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ अधिनियम की धारा 8 और 18 के तहत आरोप तय किए, जिससे आरोपी ने इनकार कर दिया और परीक्षण का दावा किया।

विद्वान सत्र न्यायाधीश, बारां ने माना कि आरोपी दोषी था, उसे अधिनियम की धारा 8 और 18 के तहत दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अपील में, आरोपी प्रत्यर्थी का मुख्य रुख यह था कि अधिनियम की धारा 42 और 50 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया की चूंकि आरोपी की सार्वजनिक सड़क पर तलाशी ली गई थी और प्रतिबंधित सामग्री जब्त कर ली गई थी, इसलिए अधिनियम की धारा 43 में संलग्न स्पष्टीकरण के मद्देनजर अधिनियम की धारा 42 का कोई उपयोग नहीं था। यह ध्यान दिया गया कि प्रेम शंकर (अभियोजन पक्ष का गवाह–2) जो अधिनियम की धारा 42 के तहत एक अधिकृत अधिकारी थे, ने आरोपी को पुलिस उपाधीक्षक (अभियोजन पक्ष का गवाह–3) की उपस्थिति में तलाशी लेने के अपने अधिकार के बारे में सूचित किया, जो एक राजपत्रित अधिकारी थे और घटनास्थल पर मौजूद थे और अगर वह चाहे तो उसे किसी भी दंडाधिकारी के पास ले जाया जा सकता है। अभियुक्त ने

पुलिस उपाधीक्षक की उपस्थिति में अपनी तलाशी के लिए सहमति व्यक्त की और तदनुसार अभियोजन पक्ष के गवाह–3, पुलिस उपाधीक्षक की उपस्थिति में तलाशी ली गई, जिसे अन्य गवाहों, रमेश चंद्र (अभियोजन पक्ष का गवाह –5) और राजेंद्र कुमार (अभियोजन पक्ष का गवाह–6) ने देखा। लेकिन, यह अभिनिर्धारित किया गया कि पुलिस उपाधीक्षक (अभियोजन पक्ष का गवाह–3) की उपस्थिति में आरोपी की तलाशी के लिए दी गई सहमति अधिनियम की धारा 50 का पर्याप्त अनुपालन नहीं थी।

राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है। यह तथ्य नहीं है कि अभियोजन पक्ष का गवाह–3 छापेमारी दल का सदस्य था, जैसा कि उच्च न्यायालय ने देखा था। इसके अलावा, आरोपी को विकल्प दिया गया कि उसकी तलाशी अभियोजन पक्ष के गवाह–3 की मौजूदगी में की जाए या अगर वह चाहे तो उसे दंडाधिकारी के पास ले जाया जा सकता है। अभियुक्त ने स्वयं अभियोजन पक्ष के गवाह–3 की उपस्थिति में तलाशी लेने की सहमति दी थी, इसलिए कोई दुर्बलता नहीं थी।

जवाब में, आरोपी–प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने कहा कि राजपत्रित अधिकारी पर अधिक भरोसा किया जाता है और इसलिए, उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि आरोपी को किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाना चाहिए था।

निर्णय लिया जाने वाला एकमात्र प्रश्न धारा 50 का कथित गैर–अनुपालन है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:

> "*50. शर्तें जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी*
> (1) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत कोई अधिकारी धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, तो वह, यदि ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हो, तो ऐसे व्यक्ति को अनावश्यक देरी के बिना, धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग या निकटतम दंडाधिकारी या निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाएगा।
>
> (2) यदि ऐसी मांग की जाती है, तो अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि वह उसे राजपत्रित अधिकारी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट दंडाधिकारी के सामने नहीं ला सके।
>
> (3) राजपत्रित अधिकारी या दंडाधिकारी जिसके सामने ऐसे किसी व्यक्ति को लाया जाता है, यदि उसे तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं दिखता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर देगा, लेकिन अन्यथा निर्देश देगा कि तलाशी ली जाए।
>
> (4) एक महिला को छोड़कर, कोई अन्य, किसी भी महिला की तलाशी नहीं ले सकता।"

धारा 50 को पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में ही लागू होती है। इसका विस्तार किसी वाहन या कंटेनर या बैग या परिसर की तलाशी तक नहीं है। (देखें *कलेमा तुम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य* जेटी (1999) 8 एससी 293, *पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह,* [1999] 6 एससीसी 172 और *गुरबक्स सिंह बनाम हरियाणा राज्य,* [2001] 3 एससीसी 28।) धारा 50 की भाषा स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि तलाशी परिसर, वाहनों या वस्तुओं की तलाशी के विपरीत किसी व्यक्ति के संबंध में होनी चाहिए। *बलदेव सिंह* के मामले (पूर्वोक्त) में संविधानिक पीठ द्वारा इस स्थिति को संदेह से परे तय किया गया था।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की परिशीलन करने के लिए, *बलदेव सिंह* के मामले (पूर्वोक्त) में संविधान पीठ द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायालय ने संक्षेप में यह तय नहीं किया कि धारा 50 निर्देशिका या अनिवार्य प्रकृति की थी या नहीं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट रूप से इसे अनिवार्य बनाते हैं और जांच अधिकारी (सशक्त अधिकारी) पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालते हैं कि संबंधित व्यक्ति (संदिग्ध) की तलाशी धारा 50 द्वारा निर्धारित तरीके से की जाए। व्यक्ति अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में चिंतित है कि यदि उसे इसकी आवश्यकता है, तो उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या दंडाधिकारी के समक्ष की जाएगी और यदि वह ऐसा विकल्प चुनता है, तो राजपत्रित अधिकारी या दंडाधिकारी के समक्ष उसकी तलाशी लेने में विफलता से आरोपी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अवैध वस्तुओं की बरामदगी संदिग्ध हो जाएगी और अभियुक्त को सज़ा और दोषसिद्धि ख़राब हो जाएगी। जहां अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान बरामद अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर ही दोषसिद्धि दर्ज की गई है, यह अवैध था। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूक इस तरह से मुकदमे को ख़राब नहीं कर सकती है, लेकिन अंतर्निहित पूर्वाग्रह के कारण जो एक अभियुक्त को उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में सूचित करने में चूक के कारण होगा, इससे उसकी दोषसिद्धि और सजा अस्थिर हो जाएगी। निर्णय के परिच्छेद 32 में (पृष्ठ 200 पर) इस स्थिति पर प्रकाश डाला गया था। परिच्छेद 57 में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा गया:

"(1) कि जब कोई अधिकार प्राप्त अधिकारी या पूर्व सूचना पर कार्रवाई करने वाला विधिवत अधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो, तो उसके लिए संबंधित व्यक्ति को तलाशी के लिए निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम दंडाधिकारी के पास ले जाने के अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के तहत अपने अधिकार के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। हालाँकि, आवश्यक नहीं है कि ऐसी जानकारी, लिखित रूप में हो।

(2) किसी राजपत्रित अधिकारी या दंडाधिकारी के समक्ष तलाशी के अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में संबंधित व्यक्ति को सूचित करने में विफलता एक आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह का कारण बनेगी।

(3) किसी अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा, पूर्व सूचना पर, व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में सूचित किए बिना की गई तलाशी, यदि उसे इसकी आवश्यकता है, तो उसे राजपत्रित अधिकारी या दंडाधिकारी के समक्ष तलाशी के लिए ले जाया जाएगा और यदि वह ऐसा विकल्प चुनता है, तो विफलता होगी। किसी राजपत्रित अधिकारी या दंडाधिकारी के सामने उसकी तलाशी लेने से मुकदमा तो ख़राब नहीं होगा लेकिन अवैध वस्तु की बरामदगी संदिग्ध हो जाएगी और अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा ख़राब हो जाएगी, जहाँ दोषसिद्धि, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर दर्ज की गई है।

(4) यह कि धारा 50 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का विधिवत पालन किया गया है या नहीं, यह न्यायालय द्वारा मुकदमे में दिए गए सबूतों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। उस मुद्दे पर किसी न किसी तरीके से निष्कर्ष निकालना दोषसिद्धि या दोषमुक्ति का आदेश दर्ज करने के लिए प्रासंगिक होगा। मुकदमे में अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करने का अवसर दिए बिना, कि धारा 50 के प्रावधानों और, विशेष रूप से, उसमें प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का विधिवत अनुपालन किया गया था, आपराधिक मुकदमे को कम करने की अनुमति नहीं होगी।

(5) जिस संदर्भ में खोजे जाने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए धारा 50 में सुरक्षा शामिल की गई है, हम इस पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं कि धारा 50 के प्रावधान अनिवार्य हैं या निर्देशिका, लेकिन उस विफलता को मानते हैं संबंधित व्यक्ति को धारा 50 की उपधारा (1) से प्राप्त उसके अधिकार के बारे में सूचित करें और तस्करी के संदिग्ध की बरामदगी और आरोपी की दोषसिद्धि और सजा को कानून की नजर में खराब और अस्थिर बनाएं।

(6) अधिनियम की धारा 50 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन में की गई तलाशी के दौरान किसी आरोपी के पास से जब्त की गई अवैध वस्तु को आरोपी के अवैध कब्जे के सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, हालांकि कोई अन्य सामग्री बरामद की गई है। उस तलाशी के दौरान, किसी अवैध तलाशी के दौरान उस सामग्री की बरामदगी के बावजूद, किसी आरोपी के खिलाफ अन्य कार्यवाहियों में अभियोजन पक्ष पर भरोसा किया जा सकता है।"

इसमें कोई विवाद नहीं है कि धारा 50 के तहत दी जाने वाली आवश्यक जानकारी को संप्रेषित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रपत्र निर्धारित या अभिप्रेत नहीं है। चूंकि कोई विशिष्ट तरीका निर्धारित या अभिप्रेत नहीं है, इसलिए न्यायालय को सूचना के स्वरूप को नहीं, बल्कि उसके सार को देखना होगा। धारा 50 की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है या नहीं यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर किया जाना है और इसका कोई व्यापक सामान्यीकरण और/या सीधा रास्ता नहीं हो सकता है।

धारा 50 में कोई आत्म–दोषारोपण शामिल नहीं है। यह केवल एक प्रक्रिया है जो किसी आरोपी (संदिग्ध) के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है और उसे किसी निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष यदि आवश्यक हो तो तलाशी लेने के उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में जागरूक किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना प्रतीत होता है कि बाद के चरण में आरोपी (संदिग्ध) यह दलील न दे कि सामान उस पर लगाया गया था या वह सामान उसके पास से बरामद नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो खोज की प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्रधानता दी गई है। *रघबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य*, [1996] 2 एससीसी 201 में, धारा 50 के वास्तविक सार को निम्नलिखित तरीके से उजागर किया गया था:

"8. जो प्रश्न हमें संदर्भित किया गया है उस पर मनोहर लाल बनाम राजस्थान राज्य (एसएलपी (आपराधिक) संख्या 184/1996 में आपराधिक एमपी संख्या 138/96) में 22.1.1996 को दो विद्वान न्यायमूर्तिगण की पीठ द्वारा विचार किया गया था। हम में से एक (न्यायाधीश वर्मा) ने पीठ की ओर से बोलते हुए कहा:

"एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 से यह स्पष्ट है कि आरोपी को दिया गया विकल्प केवल यह चुनना है कि क्या वह तलाशी लेने वाले अधिकारी द्वारा या निकटतम उपलब्ध राजपत्रित अधिकारी या निकटतम उपलब्ध दंडाधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहेगा। निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम दंडाधिकारी का चयन तलाशी लेने वाले अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि आरोपी द्वारा।"

9. हम पूर्वोक्त *मनोहर लाल* के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं।

10. किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तुएं पाए जाने पर जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवैध हैं, उसे यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि वह इसके प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर रहा था और यह उसे गंभीर दंड के लिए उत्तरदायी बनाता है। इसलिए, यह अधिनियम तलाशी लेने वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। उसे किसी वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने की आवश्यकता हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी या दंडाधिकारी हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सुविधाजनक रूप से उपलब्ध है।

11. अधिनियम की धारा 50 के तहत विकल्प, जैसा कि स्पष्ट रूप से लिखा गया है, केवल ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का है। राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में या दंडाधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का कोई और विकल्प नहीं है। धारा 50 में 'निकटतम' शब्द का प्रयोग प्रासंगिक है। तलाशी यथाशीघ्र की जानी चाहिए और, एक बार जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है वह ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प चुनता है, तो यह पुलिस अधिकारी का काम है कि वह सबसे सुविधाजनक रूप से उपलब्ध राजपत्रित अधिकारी या दंडाधिकारी की उपस्थिति में तलाशी ले।"

जैसा कि *बलदेव सिंह* के मामले (पूर्वोक्त) में उजागर किया गया है, यह देखा और परखा जाना चाहिए कि क्या धारा 50 की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। वास्तव में धारा 50 अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का प्रावधान करती है जो विशेष रूप से क़ानून द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं। एक उचित, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया गया है। अधिकार के अस्तित्व को बताने के लिए किसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त स्थिति को *प्रभा शंकर दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* (2003) एआईसमीक्षा आवेदनससीडब्ल्यू 6592 और *मदन लाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य,* (2003) 6 सर्वोच्च 382 में विस्तृत रूप से निस्तारित किया गया था।

श्रीमती कृष्णा कंवर @ ठकुराइन बनाम राजस्थान राज्य, जेटी (2004) 1 एससी 597 में इन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया और दोहराया गया।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में लागू होती है। इसका विस्तार किसी वाहन या कंटेनर या बैग या परिसर की तलाशी तक नहीं है। यह तब लागू होता है जब धारा 42 के संदर्भ में अधिकृत अधिकारी को धारा 41, 42 और 43 के प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेनी होती है। यहां तलाशी के लिए अपने विकल्प का उपयोग करने के लिए खोजे जाने वाले व्यक्ति को, धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम दंडाधिकारी की उपस्थिति, सूचित करने की आवश्यकता होती है।

यदि व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है, तो धारा 50 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट अधिकारी उस व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या दंडाधिकारी के समक्ष लाने के लिए हिरासत में ले सकता है, जैसा भी मामला हो। जैसा कि रघबीर सिंह के मामले (पूर्वोक्त) में देखा गया था, अधिनियम उस व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए एक सुरक्षा प्रदान करता है कि उसे एक वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने की आवश्यकता हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी या दंडाधिकारी हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सुविधाजनक रूप से उपलब्ध है। एनडीपीएस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि यदि कोई राजपत्रित अधिकारी, चाहे वह किसी विशेष पद का पुलिस अधिकारी ही क्यों न हो, आरोपी को हिरासत में लेते समय पास में मौजूद है, तो आरोपी से पूछा जा सकता है कि क्या वह उस अधिकारी या

दंडाधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहेगा। आरोपी–प्रत्यर्थी द्वारा अपनाए गए रुख का आधार, जिसे उच्च न्यायालय का समर्थन मिला, वह यह है कि यदि वह छापेमारी दल का सदस्य है तो धारा 50 की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है, और वर्तमान मामले के तथ्यों पर किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं था क्योंकि व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उपाधीक्षक अभियोजन पक्ष के गवाह –3 मौके पर पहुंचे थे।

जैसा कि *रघबीर सिंह* के मामले में उल्लेख किया गया है, अभियुक्त को दिया गया विकल्प केवल यह चुनना है कि क्या वह तलाशी लेने वाले अधिकारी द्वारा या निकटतम उपलब्ध राजपत्रित अधिकारी या निकटतम उपलब्ध दंडाधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहेगा। निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम दंडाधिकारी का चयन तलाशी लेने वाले अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि आरोपी द्वारा। मौजूदा मामले में आरोपी को सभी विकल्पों से अवगत कराया गया और उसने खुद पुलिस उपाधीक्षक (अभियोजन पक्ष का गवाह –3) की मौजूदगी में तलाशी लेने का विकल्प चुना।

धारा 41, 42, 43 या धारा 50 छापा मारने वाले पक्ष की बात नहीं करती। धारा 41 (2) ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्रगणित विभाग के राजपत्रित पद के किसी भी अधिकारी या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी (लेकिन चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से पद में वरिष्ठ) द्वारा गिरफ्तारी की बात करती है। धारा 41 की उपधारा (1) के तहत उक्त प्रावधान में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए एक वारंट एक अधिकारी को संबोधित किया जा सकता है। धारा 42 अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाने वाली अनुमत कार्रवाई से संबंधित है। धारा 43 धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग के एक अधिकारी की शक्ति से संबंधित है। धारा 41, 42 और 43 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाला अधिकारी निर्धारित कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से दूसरों की सहायता ले सकता है।

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष सही होते यदि तलाशी लेने का प्रस्ताव करने वाला अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होता और वह धारा 50 के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प देता। उस स्थिति में, धारा 50 की आवश्यकता पूरी नहीं होगी क्योंकि खोज को प्रभावित करने का प्रस्ताव करने वाला अधिकारी दोहरी क्षमता में कार्य नहीं कर सकता है; पहला किसी व्यक्ति की तलाशी के लिए धारा 42 के तहत अधिकृत अधिकारी के रूप में और दूसरा राजपत्रित अधिकारी के रूप में जिसकी उपस्थिति में आरोपी तलाशी का विकल्प चुन सकता है।

एनडीपीएस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि तलाशी एक वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में की जाती है, खोज में पारदर्शिता और प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए इसे कानून में एक सिद्धांत के रूप में नहीं माना जा सकता है कि यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी साथ होता है अधिकृत अधिकारी (जिसे उच्च न्यायालय ने छापेमारी दल का सदस्य बताया है) की स्थिति अलग होगी। उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि अधिकारी की ओर से पक्षपात हो सकता है क्योंकि वह अधिकृत अधिकारी के साथ था।

इसलिए, उच्च न्यायालय का यह मानना सही नहीं था कि अभियोजन पक्ष के गवाह –3 की उपस्थिति में तलाशी धारा 50 की आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं थी। किसी भी प्रगणित अधिकारी श्रेणी की उपस्थिति में की जा रही तलाशी पर जोर दिया जा रहा है। *एस जीवनाथम बनाम स्टेट थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, हस्तांतरित आवेदनन,* [2004] 5 एससीसी 230 में, अभियुक्त द्वारा यह तर्क दिया गया था कि शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की गई थी, धारा 8(सी) के साथ पढ़ी गई अधिनियम की धारा 20(बी)(ii) के संदर्भ में दोषसिद्धि ख़राब हो गई थी। *पुलिस, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निरीक्षक, तिरुचिरापल्ली, हस्तांतरित आवेदनन बनाम जयापॉल,* [2004] 5 एससीसी 223 द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया था। यह देखा गया

कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया था जांच में पूर्वाग्रह पैदा हुआ था या आरोपी के खिलाफ पक्षपातपूर्ण था। मौजूदा मामले में, आरोपी को उसके अधिकारों और प्रयोग किये जाने वाले विकल्पों के बारे में सूचित किया गया। उन्होंने अभियोजन पक्ष के गवाह–3 की उपस्थिति में तलाशी लेने की सहमति दी। इसलिए, धारा 50 का अनुपालन न करने का आग्रह करना भी उसके लिए खुला नहीं था।

वास्तव में *एस जीवननाथम* मामले (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि जो अधिकारी शिकायतकर्ता था वह जांच अधिकारी नहीं हो सकता। पूर्वाग्रह या पक्षपात के प्रश्न को स्थापित करना होगा न कि अनुमान लगाना होगा। किसी भी स्थिति में, उस संबंध में कोई कानूनी धारणा नहीं बनाई जा सकती। इस समय, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 50 की उपधारा (3) के तहत, राजपत्रित अधिकारी या दंडाधिकारी जिसके सामने जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है उसे लाया जाता है, किसी दिए गए मामले में, यह मान सकता है कि वहां तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं है और व्यक्ति को तुरंत "मुक्त" कर दिया जाएगा। अन्यथा, वह तलाशी लेने का निर्देश देगा। धारा 50 की उपधारा (3) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'मुक्ति' का प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है कि नजरबंदी समाप्त हो गई है।

हिरासत में लेने, तलाशी लेने और गिरफ्तार करने की शक्तियां धारा 41(2), 42 और 43 द्वारा प्रदान की गई हैं। धारा 42(एल)(डी) के तहत अधिकृत अधिकारी सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच हिरासत में ले सकता है और तलाशी ले सकता है और यदि वह, है। जिसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने अधिसूचित औषधि या पदार्थ से संबंधित अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध किया है, उचित समझता है तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता। गिरफ्तारी का सवाल तब आता है जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है और उसकी तलाशी ली जाती है और उसके बाद यदि अधिकारी को लगता है कि उचित गिरफ्तारी इस आधार पर की जा सकती है कि अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि हिरासत में लिए गए और तलाशी लिए गए व्यक्ति ने अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध किया है। यह नहीं कहा जा सकता कि अधिकृत अधिकारी के साथ गया व्यक्ति प्रस्तावित तलाशी के लिए 'नहीं' नहीं कह सकता, भले ही उसे तलाशी के लिए कोई उचित आधार न दिखे। यह एक वरिष्ठ अधिकारी पर निष्पक्ष और उचित कार्य करने के लिए लगाया गया विधायी विश्वास है। इसलिए, यह अभियुक्त पर निर्भर है कि वह पूर्वाग्रह स्थापित करे जो मुकदमे में किया जाना है। मामले के तथ्यों पर वास्तव में ये सवाल नहीं उठते. निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष यदि आवश्यक हो तो तलाशी लेने की आवश्यकता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन अधिकारियों पर तलाशी लेने का कर्तव्य सौंपा गया है, वे उचित तरीके से आचरण करते हैं और कोई नुकसान या गलत नहीं करते हैं जैसे कि किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा आपत्तिजनक दवा का रोपण और किसी भी झूठे सबूत के निर्माण को रोकना। संक्षेप में प्रावधान का उद्देश्य कष्टप्रद खोज, अनुचित व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करना और निर्दोष व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है। वास्तव में, गिरफ्तारी से बचने और जांच को शुरू में ही बाधित करने के लिए, जिससे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके, धारा 50 की उपधारा (3) में एक वैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। शक्ति दंडाधिकारी या राजपत्रित अधिकारी में निहित की गई है जिसके समक्ष संबंधित व्यक्ति को उप–धारा (2) के तहत की गई उसकी मांग पर लाया जाता है कि उसकी संतुष्टि पर कि तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं है, औपचारिक कार्यवाही के बिना उस व्यक्ति को तुरंत मुक्त कर दिया जाए। परिणामस्वरूप, तलाशी तभी होती है जब वह ऐसे व्यक्ति को सेवामुक्त करने से इंकार कर देता है।

सबसे पहले, जैसा कि ऊपर बताया गया है, व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के बाद अभियोजन पक्ष का गवाह–3 घटनास्थल पर पहुंचा और अधिकृत अधिकारी द्वारा तलाशी किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। दूसरे, प्रत्यर्थी–अभियुक्त को विकल्प दिया गया था कि क्या वह अभियोजन पक्ष के गवाह–3 या निकटतम

दंडाधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहेगा। उन्होंने अभियोजन पक्ष के गवाह–3 की उपस्थिति में तलाशी लिए जाने के अपने विकल्प का प्रयोग किया।

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं। अपरिहार्य परिणाम यह है कि उच्च न्यायालय का निर्णय बचाव योग्य नहीं है और उसे रद्द कर दिया जाता है तथा विचारण न्यायालय का निर्णय बहाल कर दिया जाता है। अभियुक्त को शेष सजा काटने के लिए तुरंत हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा। अपील की अनुमति है।

बी.बी.बी. अपील को अनुमती दी गयी।

विक्रांत ठाकुर की देखरेख में सुमीत कपूर द्वारा अनुवादित।